

Newspaper Clips

February 9, 2013

Amar Ujala ND 9/02/2013

P3

मैली यमुना केस में रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को यमुना नदी की सफाई के मामले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मंत्रालय को चार हफ्ते में यह रिपोर्ट दिल्ली और रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के निदेशकों की ओर से दी जाने वाली रिपोर्ट समेत दाखिल करनी है। सर्वोच्च अदालत ने 11 दिसंबर को दोनों आईआईटी निदेशकों को यमुना नदी की सफाई के लिए परियोजना तैयार करने के लिए कहा था। बीस साल में 12 हजार करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद यमुना की स्थिति ज्यों की त्यों रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए नए सिरे से परियोजना पर काम करने का निर्देश दिया था।

चीफ जस्टिस अल्लमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अदालत के सहायक रंजीत कुमार ने कहा कि मंत्रालय की ओर से 12 जनवरी की बैठक का कोई भी दस्तावेज नहीं पेश किया गया है और अगली बैठक 12 फरवरी को होने वाली है। सरकार यमुना की सफाई को लेकर गंभीर नहीं है।

स्तरीय शिक्षा बिना अधूरी तस्वीर

शशांक द्विवेदी

देश-समाज के विकास में उच्च और तकनीकी शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। तमाम ताकतवर व समृद्ध देशों की सफलता का बड़ा कारण विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा ही है। अमेरिका, चीन, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, ताईवान, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की आर्थिक प्रगति को उनकी विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा से जोड़कर ही समझा जा सकता है। विकास से जुड़े विभिन्न मामलों पर जब भी एशिया की चर्चा होती है तो चीन और भारत की तुलना स्वाभाविक रूप से की जाती है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक पत्रिका द इकनॉमिस्ट ने एशिया की दोनों प्रमुख ताकतों का विकास के विभिन्न मुद्दों मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी विकास आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया। जिसमें हर स्तर और आयाम में चीन अब भी भारत से काफी आगे है। भारत जिस स्तर पर आज है, उसे चीन सालों पहले हासिल कर चुका है। विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा विकसित करने के मामले में भी चीन हमसे बहुत आगे है।

1949 में चीन और 1947 में भारत की उच्च शिक्षा का रूप बहुत सीमित था। 1949 में चीन में 205 विश्वविद्यालय और 1947 में भारत में 26 विश्वविद्यालय थे। 1990 में चीनी अर्थव्यवस्था में आई तेजी के बाद कॉलेज व विश्वविद्यालयों को उभरने और विकसित होने का मौका दिया गया। आज चीन में दो हजार से अधिक विश्वविद्यालय व संस्थान उच्च शिक्षा, तकनीक, प्रबंधन और चिकित्सा की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए जाने जाते हैं जहां पढ़ने के लिए विदेशी छात्र आकर्षित हो रहे हैं। चीन के उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक यहां 2011 में विदेशी छात्रों की संख्या 2.60 लाख से अधिक थी। पिछले 20 सालों में चीन की सरकार ने अपने कुछ विश्वविद्यालयों जैसे बीजिंग, सिनहुआ, शंघाई, जिओटांग और फूडान आदि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया, जिनकी विश्व रैंकिंग है।

देश में उच्च शिक्षा की स्थिति पर बात करें तो शिक्षर पर कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईटी जैसी सौ संस्थाएँ हैं, जिनमें

मुश्किल से एक लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। दूसरी तरफ 538 विश्वविद्यालय और 26478 उच्च शिक्षा संस्थानों में 1.60 करोड़ युवा भीड़ की तरह पढ़ने-लिखने की कवायद भर करते हैं। ग्रास एनरोलमेंट के लिहाज से यह 12 प्रतिशत है जो ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। जबकि केंद्र सरकार ने 2020 तक 30 प्रतिशत एनरोलमेंट का लक्ष्य रखा है। देश में संस्थानों की भीड़ बढ़ाने के लिए तीस वर्षों में अनेक निजी संस्थान और डीम्ड विश्वविद्यालय खुले हैं, जिनका कोई मानक और स्तर नहीं है। इसी वजह से तकनीकी शिक्षा के मौजूदा सत्र में इस बार पूरे देश में ढाई लाख से ज्यादा सीटें खाली रह गई थीं। 153 विश्वविद्यालयों तथा 9875



कॉलेजों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा ही नहीं है।

चीन ने शिक्षा प्रणाली में दो-तीन दशकों में किए बदलावों से अपनी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया है। वहां तकनीकी और उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या वृद्धि के साथ-साथ गुणवत्ता में भी उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। उसने 1990 के मध्य में प्रोजेक्ट 211 के अंतर्गत विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों, उच्च शोध संस्थानों और तकनीकी हब की बड़ी श्रृंखला तैयार की है। चीन जानता है कि आर्थिक सर्वश्रेष्ठता बेहतर तकनीकी शिक्षा, शोध और विकास पर ही निर्भर है। 1995 से 2005 के बीच वहां पीएचडी करने वालों की संख्या पांच गुना बढ़ी है। पीएचडी ही नहीं, बल्कि शोध पत्रों व पेटेंट के मामले में भी हम चीन से काफी पीछे हैं। इसी पर संसद की प्राक्कलन समिति ने पिछले दिनों लोकसभा में प्रस्तुत अपनी 17वीं रिपोर्ट में देश में उच्च शिक्षा की हालत पर गहरी चिंता जताई है। सैम पित्रोदा के नेतृत्व

वाले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) ने स्वीकारा है कि भारत में उच्च शिक्षा का संकट बहुत गहरा है।

पिछले दिनों क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया के शीर्षस्थ 200 विश्वविद्यालयों की सूची में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान का नाम नहीं है। विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा की तीन लोकप्रिय रैंकिंग में एक है क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसका निर्धारण शोध की गुणवत्ता, शैक्षणिक प्रतिष्ठा और नियोजकों की साख के आधार पर किया जाता है। कुछ लोग इस तरह की रैंकिंग नहीं मानने का दावा कर सकते हैं लेकिन वैश्वीकरण और खुली अर्थव्यवस्था के इस दौर में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा तो होगी ही। इस रैंकिंग की एशिया के 200 शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों की सूची में जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और ताईवान का प्रभुत्व दिखता है। भारत एशिया की सूची में पांचवें स्थान पर है। चीन और दक्षिण कोरिया को एशिया की सूची में 50 प्रतिशत स्थान मिलना भारत के लिए बड़ा सबक है, क्योंकि 63 वर्ष पूर्व तीनों देश उच्च शिक्षा के मामले में लगभग एक स्तर पर आंके जाते थे। आज विश्व में जो उच्च शिक्षण संस्थान शिक्षर पर आसीन हैं, उनसे हमें सीखना होगा। विचार करना होगा कि क्या हम अगले 20 सालों में विश्व स्तर के सौ शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों और संस्थान बना सकते हैं? आधुनिक ज्ञान आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूर्ण क्षमता का दोहन करने के लिए भारत को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है क्योंकि उच्च शिक्षा का संकट भारत के भविष्य को सीधे-सीधे प्रभावित करेगा।

वास्तव में मौजूदा नीतियों के आधार पर विश्वस्तरीय संस्थान खड़े करना असंभव होगा। कुछ आईआईटी और आईआईएम के भरोसे हम विकसित राष्ट्र का सपना सच नहीं कर सकते। देश में तकनीकी शिक्षा की कुल सीटों में 95 फीसद निजी कॉलेजों में हैं। शेष 5 फीसद में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी हैं जहां एडमिशन के लिए बड़ी होड़ है लेकिन देश के विकास के लिए बाकी 95 प्रतिशत कॉलेजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें विश्वस्तरीय संस्थान खड़े करने के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय नीति की जरूरत है, जो गुणवत्ता, पारदर्शिता, स्वायत्तता, विकेंद्रीकरण, जवाबदेही, विविधता और विश्व दृष्टि जैसे मूल्यों पर आधारित हो। देश के युवाओं को व्यावहारिक और रोजगारपरक तकनीकी ज्ञान मिले, जिसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से प्रयोग किया जा सके।

Nasa to land craft on asteroid in 2018

TIMES NEWS NETWORK

London: In the first such mission, Nasa is planning to launch a spacecraft to an asteroid in 2016 and use a robotic arm to pluck samples from a Near Earth Asteroid (NEA) that could better explain our solar system's formation and how life began. The mission will be the first US mission to carry samples from an asteroid back to Earth.

The mission is being called Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith

Explorer or OSIRIS-Rex. After traveling two years, OSIRIS-REx will approach the primitive NEA designated 1999 RQ36 in 2018, discovered back in 1999.

Once within three miles of the asteroid, the spacecraft will begin six months of comprehensive surface mapping. It gradually will move closer to the site, and the arm will extend to collect more than two ounces of material for return to Earth in 2023. Dante Lauretta from University of Arizona is the mission's principal investigator.